Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

The Nationalist

ISSN 2454-9401

Issue : May 2018

Modi-Putin Informal Summit at Sochi – laying a stronger foundation

How NDA Government Schemes Have Helped the Poorest of the Poor

सुशासन बना राजनीति का केंद्रीय बिंदु, आम नागरिकों के मन में बढ़ा आत्मसम्मान एवं विश्वास का भाव

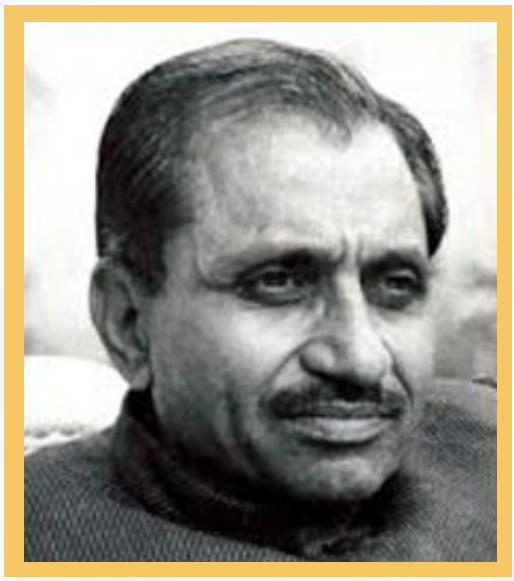

"Let him consider the cause and not the caste; go with the worthy rather than with the winner. Choose the right man and see that the man you choose wins; that will be your victory."

-Pt. Deendayal Upadhyaya

The Nationalist
Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Editorial Advisors:

Shakti Sinha, IAS (Rtd)
Former Power & Finance
Secretary Govt. of Delhi

Dr. Anirban Ganguly
Director, SPMRF

Dr. Shiv Shakti Bakshi
Executive Editor, Kamal Sandesh

Dr. Vijay Chauthaiwale
In Charge BJP Foreign Affairs Department
& Convener, Overseas Friends of BJP

Dr. Dhananjay Singh
(Assistant Professor)
Jawaharlal Nehru University

Professor Santishree D. Pandit
Professor
Savitribal Phule Pune University &
Vice President - Indian Politics Science Association

Dr. Amit Singh
Assistant Professor ARSD College,
Delhi University

Amit Malviya
National In Charge, IT & Social
Media Vibhag, BJP

Research Team

- Shivanand Dwivedi
- Ajit Jha
- Shailendra Kumar Shukla
- Shubhendu Anand
- Ayush anand
- Vaibhav Chadha
- Amit Kumar

Layout
LunaCreatives.in

CONTENT

EDITORIAL

- Prime Minister Narendra Modi Poses a Challenge to the Liberal Fundamentalists
  - Dr. Anirban Ganguly

PM MODI'S VISION

- Salient Points of PM Modi's speech at event marking the dedication of Kishanganga Hydro Electric Project to the nation in Srinagar on 19 May, 2018
- Salient Points of PM Modi's address at the convocation of Visva Bharti University at Santiniketan in West Bengal on 25 May, 2018

SPECIAL ARTICLE

- Modi-Putin Informal Summit at Sochi – laying a stronger foundation - ***Ambassador Asoke Mukerji***
- Chidambaram's jobs debate debunked: Speaking Truth to Power or Spewing Lies on the Nation? - ***Philip Christopher***
- आर्थिक मोर्चे पर 4 साल की मोदी सरकार का लेखा-जोखा - ***हर्षवर्धन त्रिपाठी***

POLICY ANALYSIS

- How NDA Government Schemes Have Helped the Poorest of the Poor - ***Ananth Krishna***
- National Health Policy, 2017 : A Paradigm Shift Towards Making India Healthy - ***Madhura Joshi***
- आर्थिक मजबूती, पारदर्शी शासन और कल्याणकारी नीतियों के चार वर्ष!
  - सतीश सिंह
- 'इसे मोदी इफेक्ट ही कहेंगे कि 30 महीने का काम 17 महीने में ही पूरा हो गया'
  - रमेश कुमार दुबे
- चार सालों में सुशासन और विकास के हर मोर्चे पर कांग्रेस से बेहतर साबित हुई है मोदी सरकार ! - ***अभय सिंह***

POLITICAL COMMENTARIES

- सुशासन बना राजनीति का केंद्रीय बिंदु, आम नागरिकों के मन में बढ़ा आत्मसम्मान एवं विश्वास का भाव - ***भूपेंद्र यादव***

EVENT @ SPMRF

- ***Discussion on "Dr Syama Prasad Mookerjee: Life and Legacy in the Present Context of West Bengal" at ICCR, Kolkata, West Bengal on 19th May 2018***

Prime Minister Narendra Modi Poses a Challenge to the Liberal Fundamentalists

Dr. Anirban Ganguly

Four years have passed since Prime Minister Narendra Modi was elected to the office of the Prime Minister of India; four summers have gone by since he took oath of office. For those who have been inspired by and have traditionally identified with the spirit of Bharat, civilisational India, India of the inner realm, the India that was being asphyxiated by the stranglehold of liberal fundamentalism, for them the rise of Narendra Modi, his victory and his imprint are of phenomenal significance and impact. Narendra Modi's rise signified the rise of one among their own.

In the last four years Prime Minister Modi's commitment to his vision of India, his actualizing his vision of "New India" has been unflagging and unfailing. The articulation and actualization are so energetic, convincing and pragmatic that it continues to attract adherents in India and attention across the world. The mainstreaming of the marginalized has been his priority. It is a promise he made to us and to himself on the day he crossed the threshold of Parliament. He has not deviated from that.

Some liberal fundamentalists sneered at Narendra Modi, while some wrote reams trying to prove that the electorate was unwise in electing a leader like him. Just because their predictions and impositions had been rejected or refused and simply because it was Modi who was elected, they questioned the mandate itself. It would not have been questioned had it been a Gandhi dynast; they are entitled to rule India.

Others got down to a futile exercise of trying to analyse the May 2014 electoral verdict and peddled the theory that Narendra Modi had just won 31 percent of the vote and therefore can never be the leader of whole of India. The prerogative of ruling India, for these liberal fundamentalists, is reserved for an Oxbridge educated dummy leader or a dynast with no qualification or talent except that he was born into a family, whose members have always felt that they were born to rule India. However, Narendra Modi has always made it clear; he works for those who have voted for him and unreservedly, for those who have not voted for him. When was it last that such a position was articulated in India's public life?

No other leader in the past thirty years has been so scrutinized, so pilloried, so admired, so worshiped and so inspiring, as has been Narendra Modi. While his mass acceptability, the mass percolation of his vision and conviction is increasing by the day, his presence continues to unnerve liberal fundamentalists who feel a tremendous sense of opposition now to their false narratives of India and to their false submissions engineered by those narratives.

Narendra Modi has repeatedly challenged the liberal fundamentalists in these last four years, which is why they see in him their nemesis. In his triumph they see their doom…

Salient Points of PM Modi's speech at event marking the dedication of Kishanganga Hydro Electric Project to the nation in Srinagar on 19 May, 2018

» एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आप सभी के बीच आने का अवसर मुझे मिला है आपका अपनापन, आपका स्नेह ही है जो मुझे बार-बार यहां खींच लाता है। बीते चार वर्ष में ऐसा कोई साल नहीं रहा जब मेरा यहां आना ना हुआ हो।

» श्रीनगर में बाढ़ के बाद की दीवाली मैंने यहां पीड़ितों के बीच बिताई थी। इसके अलावा सीमा पर तैनात जवानों के साथ दीवाली मनाने का भी मुझे सौभाग्य मिला था। और आज जब रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है तब भी मैं आपके बीच में हूं।

» ये महीना पैगम्बर मोहम्मद साहब की शिक्षा और उनके सन्देश को याद करने का अवसर है। उनके जीवन से समानता और भाईचारे की सीख ही सही मायने में देश और दुनिया को आगे ले जा सकती है।

» ये भी सुखद संयोग है कि रमज़ान के इस मुबारक महीने में ही हम यहां एक बहुत बड़े सपने के पूरा होने पर इकट्ठा हुए हैं। आज मुझे किशनगंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है।

» ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में नए आयाम जोड़ने के लिए तैयार है। इस अवसर पर मैं आप सभी को बधाई देता हूं।

» इससे राज्य को सिर्फ मुफ्त ही नहीं बल्कि पर्याप्त बिजली मिलेगी। अभी जम्मू कश्मीर को जितनी बिजली की आवश्यकता होती है, उसका एक बड़ा हिस्सा देश के दूसरे हिस्से से पूरा किया जाता है। 330 मेगावाट की इस परियोजना के शुरु होने से बिजली की कमी की समस्या को बहुत हद तक कम किया जा सकेगा।

Salient Points of PM Modi's address at the convocation of Visva Bharti University at Santiniketan in West Bengal on 25 May, 2018

» मंच पर विराजमान बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्रीमान केसरी नाथ त्रिपाठी जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जी, विश्व भारती के उपाचार्य प्रोफेसर सबूज कोली सेन जी और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद इंस्टिट्यूट के उपाचार्य पुज्य स्वमी आत्मप्रियानंद जी और यहां मौजूद विश्व भारती के अध्यापक गण और मेरे प्यारे युवा साथियों।

» प्रधानमंत्री होने के नाते मुझे देश के कई विश्वविद्यालयों के convocation में हिस्सा लेने का अवसर मिला है।

» वहां मेरी सहभागिता अतिथि के रूप में होती है लेकिन यहां मैं एक अतिथि नहीं बल्कि आचार्य यानि चांसलर के नाते आपके बीच में आया हूं।

» यहां जो मेरी भूमिका है वो इस महान लोकतंत्र के कारण है। प्रधानमंत्री पद की वजह से है। वैसे ये लोकतंत्र भी अपने आप में एक आचार्य तो है जो सवा सौ करोड़ से अधिक हमारे देशवासियों को अलग-अलग माध्यमों से प्रेरित कर रहा है।

» लोकतांत्रिक मूल्यों के आलोक में जो भी शोषित और शिक्षित होता है वो श्रेष्ठ भारत और श्रेष्ठ भविष्य के निर्माण में सहायक होता है।

» जैसे किसी मंदिर के प्रागंण में आपको मंत्रोच्चार की ऊर्जा महसूस होती है। वैसी ही ऊर्जा मैं विश्व भारती, विश्वविद्यालय के प्रागंण में अनुभव कर रहा हूं। मैं जब अभी कार से उतरकर मंच की तरफ आ रहा था तो हर कदम, मैं सोच रहा था कि कभी इसी भूमि पर यहां के कण-कण पर गुरुदेव के कदम पड़े होंगें।

» यहां कहीं आस-पास बैठकर उन्होंने शब्दों को कागज पर उतारा होगा। कभी कोई धुन, कोई संगीत गुनगुनाया होगा। कभी महात्मा गांधी से लंबी चर्चा की होगी। कभी किसी छात्र को जीवन का, भारत का, राष्ट्र के स्वाभिमान का मतलब समझाया होगा।

» वैदिक और पौराणिक काल में जिसे हमारे ऋषियों-मुनियों ने सींचा। आधुनिक भारत में उसे गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर जैसे मनिषियों ने आगे बढ़ाया। आज आपको जो ये सप्तपरिणय का गुच्छा दिया

गया है।

» बल्कि एक महान संदेश है। प्रकृति किस प्रकार से हमें एक मनुष्य के नाते, एक राष्ट्र के नाते उत्तम सीख दे सकती है।

» ये उसी का एक परिचायक, उसकी मिसाल है। यही तो इस अप्रतिम संस्था के पीछे की भावना, यही तो गुरुदेव के विचार हैं, जो विश्व भारती की आधारशिला बनी।

» भारत और बांग्लादेश दो राष्ट्र हैं लेकिन हमारे हित एक-दूसरे के साथ समंवय और सहयोग से जुड़े हुए हैं। culture हो या public policy हम एक-दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी का एक उदाहरण बांग्लादेश भवन है। जिसका थोड़ी में हम दोनों वहां जाकर के उद्घाटन करने वाले हैं। ये भवन भी गुरुदेव के vision का ही प्रतिबिंब है।

» अगर हम अफगानिस्तान जाएं तो काबुली वाला की कहानी का जिक्र हर अफगानिस्तानी करता ही रहता है। बड़े गर्व के साथ करता है। तीन साल पहले जब मैं तजाकिस्तान गया तो वहां पर मुझे गुरुदेव की एक मूर्ति का लोकार्पण करने का भी अवसर मिला था। गुरुदेव के लिए वहां के लोगों में जो आदर भाव मैंने देखा वो मैं कभी भूल नहीं सकता।

Modi-Putin Informal Summit at Sochi – laying a stronger foundation

Ambassador Asoke Mukerji

The first informal summit between India and Russia held in the Black Sea town of Sochi on 21 May 2018 yielded an interesting outcome. Prime Minister Modi called such informal meetings an "innovative element"that created "trust" between the two countries. The concept of informal summits was integrated into the India-Russia strategic partnership as "an additional engagement at the leadership level", providing the two leaders an opportunity to discuss and decide on priority issues in "consultation and coordination with each other".

The main bilateral focus of the interaction was on economic relations.It was agreed that the annual India-Russia summit to be held in October 2018 in India would have a "strong economic foundation". A "strategic economic dialogue" between India's NITI Aayog and Russia's Ministry of Economic Development

would provide the platform for implementing this objective. The dialogue would build on the work done by the joint Priority Investment Projects Group, and synergize trade, investment and economic cooperation between the two countries.

Energy cooperation was highlighted as a major pillar of this economic foundation. Russian oil supplies to India had increased "tenfold" during the past year, and there was a renewed commitment on supply of Russian liquefied natural gas. From the Russian side, the major state enterprises Rosneft and Gazprom were partnering Indian public and private enterprises (ONGC-Videsh, GAIL and Essar) in these two areas. The discussions noted that "all technical issues" regarding the construction of the fifth and sixth units of the Kudankalam nuclear power plant had been resolved, paving the way for placing these units on stream.

Five other sectors were identified as priority drivers in the economic sphere – satellite communications using the Russian GLONASS system, pharmaceuticals, chemicals, aircraft manufacturing and the automotive industry.

The two leaders agreed to begin negotiations on a free trade area between India and the Eurasian Economic Union (EAEU) in autumn 2018. President Putin characterized the EAEU as a "major Eurasian project", representing a market of 170 million people operating on WTO principles. The proposed free trade area agreement between India and the EAEU provides both sides with an identified north-south connectivity framework, to be implemented through a consultative and negotiated process.

The Sochi meeting gave the two sides an opportunity to discuss what Russian Foreign Minister Lavrov called "the trends that are unfolding in Eurasia". Foremost among these trends was the impact on the India-Russia strategic partnership of the imposition of unilateral sanctions by the United States on both Iran and Russia.Three specific areas of concern are defence cooperation between India and Russia, which is a key driver of the strategic partnership; the operationalization of the ambitious North South Transport Corridor linking Europe with Asia through Russia, Iran and India; and cooperation of both countries with Iran for energy and connectivity projects, including for land-locked Afghanistan (which was discussed in the context of India-Russia cooperation against terrorism) and Central Asia. While unilateral sanctions do not have the force of international law, the potential for retaliation by the United States on foreign companies and entities (including Indian) dealing with Russian and Iranian counterparts featuring in the US Treasury's sanctions lists is a major source of unpredictability and instability.

The informal summit at Sochi was part of a wider international response to such unilateralism. A few days earlier, India and China had held their first informal summit at Wuhan. Chancellor Angela Merkel of Germany and President Putin held an informal summit at Sochi just before the India-Russia informal summit. Both French President Emmanuel Macron and Japanese Prime Minister Shinzo Abe used their participation in the St Petersburg International Economic Forum, held just after the India-Russia informal summit, to engage in substantive bilateral consultations with President Putin.

In all these interactions, the focus was on protecting the natural development of bilateral trade and economic relations, especially in the energy sector. Germany is Russia's second largest trading partner (after China) and has invested $18 billion in the Russian economy, while Russia supplies one third of Europe's natural gas requirement. This is expected to increase following the completion of the Nord Stream 2

pipeline project. Over 5000 German companies operate in Russia today, with a turnover of $50 billion, employing 270,000 Russians. France has invested $15 billion in the Russian economy, and over 500 French companies are active in Russia. Russia supplies 25% of the uranium used by France's nuclear energy sector. Japan's trade with Russia is worth $18 billion, and the two leaders have agreed on 8 areas of bilateral engagement, prioritizing high technology cooperation, energy, the automobile industry and healthcare. Russia is a new source for supply of natural gas to Japan from the Sakhalin-2 project, while 9% of Japan's oil imports are from Russia.

The Sochi informal summit is expected to influence the forthcoming Shanghai Cooperation Organization Summit scheduled to be held in Qingdao (China) on 9-10 June 2018, in which India will be participating for the first time as a full and equal member.

The reference to the shared perspectives of India and Russia as "major powers with common responsibilities for maintaining global peace and stability" in the discussions at Sochi underlined the relevance of the Indo-Pacific region. In the western Indo-Pacific/West Asia, both India and Russia have significantly enhanced their diplomacy. Three issues are relevant for India's espousal of an "open" Indo-Pacific region. First, assured supplies and stable prices of energy from the western Indo-Pacific for world markets. India's growing economy imports almost 70% of its energy from West Asia. Second, political stability in the western Indo-Pacific, centering around Iran, to ensure the livelihood and remittances of foreign workers in the Gulf, including the 8 million Indians who remit almost $40 billion annually to India's household economy. Third, the need to keep open the sea lane of communication linking the Red Sea through the Bab-al-Mandab straits to the Indian Ocean. This lane carries the bulk of India's trade with the West (including the European Union, United States and Russia), as well as the underwater fibre optic cables which connect India to the global internet.Today, 40% of India's GDP is contributed by trade. The role of theIndia-Russia strategic partnership in protecting these vital interests cannot be understated.

The Sochi informal summit between India and Russia focused on the "deep trust, mutual respect and goodwill that characterizes relations between India and Russia". The two leaders called for "concrete outcomes" for the next annual India-Russia summit this October.

One such concrete outcome could be a decision to create an India-Russia Forum for multi-stakeholder interaction, based on shared civilizational values and global aspirations of both countries, to drive the future development of the India-Russia strategic partnership. Such public diplomacy platforms play an important role in Russia's relations with Germany and France. The German-Russia Forum is designed to "preserve old bridges, build new bridges". The Trianon Dialogue was launched by the France-Russia summit in 2017.

An India-Russia Forum would build on the vision of the India-Russia strategic partnership launched during the 2000 New Delhi Summit between Prime Minister Atal Bihari Vajpayee and President Putin. It would integrate the contemporary realities of India and Russia to give substance to the vision of Sanskriti se Suraksha (Culture to Defence) articulated by Prime Minister Modi at the 18th India-Russia summit in St Petersburg in 2017.

[Ambassador Asoke Mukerji was India's Permanent Representative to the United Nations (2013-2015) and India's Deputy Ambassador to the Russian Federation (2001-2005). The views expressed are personal.]

Chidambaram's jobs debate debunked: Speaking Truth to Power or Spewing Lies on the Nation?

Philip Christopher

The NDA government led by Prime Minister Narendra Modi is working towards doubling India's economy to $5 trillion by 2025 and doing so allows India to emerge as a global economic super power. The democratic mandates in the North East are clearly towards ensuring that India remains on the path of economic development by choosing development over corruption, wider participatory democracy over narrow dynastic politics and progress over regression. The people recognise that an India cleansed of corruption is paramount to achieving higher levels of economic growth than what the country experienced. While the BJP government is continuing to systematically eradicate corruption, it is also ensuring that progressive economic policies required for economic growth are implemented continuously without any hinderance. One such policy is 'Skill India', which is perhaps one of the most important initiatives to tackle unemployment.

India's diverse workforce is categorized into agriculture - 47%, industry - 22% and services - 31%. India adds 12 million new workers to its workforce every year and more than 90% of this workforce is in the informal sector. The government's employment generation programmes are aligned to these market realities and do not infringe on the freedom of individuals to pursue employment options on the basis of their individual choice. Currently, over 40 skill development programmes are being implemented by over 18 central ministries such as the PMKVY, DDU-GKY, DAY and SDIS. On the other hand, programmes such as the Mudra Yojana, RSETI, Aajeevika, NIESBUD and SJSRY support micro entrepreneurs opting for self-employment. Therefore, these programmes collectively give individuals the option to choose between wage employment or setting up their own businesses. This is in line with the BJP's 2014 election manifesto "Economic freedom implies that Government will not get in the way of the freedom of individuals to start and operate legitimate businesses. Increased economic freedom will break open the economic space to new entrants, especially in the form of small and medium-enterprises, creating jobs and prosperity."

In the more recent past, the Congress party has made job creation a major political issue and has spurred a political debate in the country. Chidambaram sets two pre-conditions for this debate: recognise and acknowledge the distinction between 'job' and 'self-employment' and the creation of 'aspirational jobs'.

While there is a clear and obvious distinction

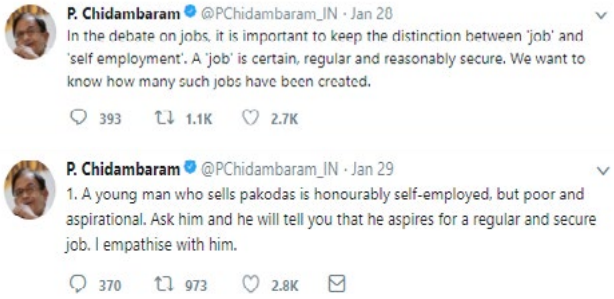

between rozgar (employment) and kaam (job), it is important to note that the discussion was about the achievements of the Prime Minister's Mudra Yojana, an example of which, as explained by the Prime Minister, is a Mudra Scheme beneficiary setting up a pakoda shop to secure his livelihood. The Prime Minster himself acknowledges that this is employment (rozgar).

Employment can be either wage-employment or self-employment. And Chidambaram's response to this is:

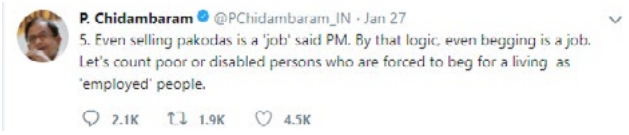

These tweets were followed by debates in parliament, media and 'pakora protests' orchestrated by the Congress party on the streets. From citing 'ILO's definition of employment' and equating 'pakora vendors to beggars', the hue and cry was aimed at clearly distinguishing between a 'job' and 'self-employment'. Chidambaram used this occasion to also accuse the BJP of distortion and deception.

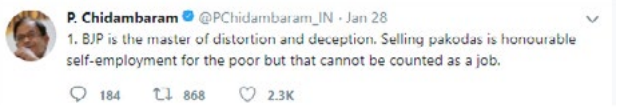

Any discussion on the outcomes of a micro credit facility programme such as the Mudra Scheme can only be about self-employment/micro entrepreneurship and not about aspirational jobs unless of course one deliberately chooses not to acknowledge the 630.52 lakh micro enterprises employing 1076.19 lakh persons. The Congress party has unfortunately chosen to deride hardworking micro entrepreneurs by equating their jobs to begging in order to score political points when in reality micro entrepreneurs are the largest job creators. In full recognition of the contribution and importance of micro entrepreneurs in not only creating jobs but also contributing to India's economic growth, the BJP-led NDA government launched the Mudra Yojana that has already benefitted 10.38 crore micro entrepreneurs. Of the total Mudra beneficiaries, 76 per cent are women and more than 50 per cent belong to the SC, ST and OBC communities. With women and deprived sections of society opting for micro entrepreneurship in such large numbers, Shri Arun Jaitley has doubled the lending target in this year's budget.

It's unfortunate that someone as distinguished as Shri P Chidambaram has gone public with such falsehoods despite glaring facts and evidence that prove just the contrary. Hard facts speak the truth that Chidambaram cannot. Chidambaram claims he empathises with the poor and aspirational and this was probably why he created the National Skill Development Corporation (NSDC), which has been a legacy baggage for the BJP government since May 2014 and was India's skill development fiasco during the UPA government's tenure. As Finance Minister and Home Minister, Mr. Chidambaram personally entrusted the NSDC, a then unregulated private company, with the responsibility to disburse public funds through its STAR and Udaan schemes to other private entities in which the NSDC itself has ownership by way of an equity stake and assets through low-cost loans. From 2008 to 2014, the NSDC and its joint initiative partners capitalized on the gaping loop holes of these two poorly regulated

and ill-conceived programmes to misappropriate hundreds of crores of public funds rather than create aspirational jobs. The Government of India's Sharada Prasad Committee dismisses any significant contribution to human capital development in India by the NSDC or its partners besides exposing a number of fraudulent practices.

Yet another instance where the Congress party failed to create aspirational jobs was under the SGSY-Special Projects wherein the programme was found wanting in quite a number of other ways as well:

Programmes like the NSDC, Star Scheme and SGSY-SP are implemented by the government to create 'relevant jobs'. Data, going back some 10 years, pertaining to job creation, is available for all to see and one will be able to see how many relevant jobs the Congress party has provided to India's aspirational youth. Unlike the Mudra Yojana, these were government efforts to secure 'jobs' not 'self-employment'. Therefore, a discussion on the outcomes of these programmes will reveal

which government has actually worked towards securing 'jobs'.

practices.

SL	Particulars	UPA I & II: SGSY – Special Projects	Deendayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY)
1	Proposal appraisal and sanction	Sanction on nomination basis and later changed to first come, first serve	Four levels of verification, quality appraisal and a scoring mechanism
2	Project timelines	Loosely defined and often not adhered to	Clearly defined SOPs with proper administrative systems in place
3	State participation	Largely absent with no role in sanction or implementation responsibility	State-led sanctions, implementation and monitoring
4	Funding / budgets	Inadequate with 25% of the project cost to be raised by training companies leading to ambiguities and fraudulent UC reporting	Fully funded by government as per approved common norms.
5	Project implementation	Poor implementation with no proper systems and procedures and failed policies	Well-defined standard operating procedures supported by progressive policymaking
6	Training centres	Poor quality, non-existent and located within workplace as market insertion support	Exclusive top-quality training centres set up with proper approvals and monitored periodically.
7	Syllabus/ course content	Not prescribed / No standards	NCVT or SSC in full compliance with NSQF to allow career and academic progression
8	Trainers	Not prescribed	ToT as prescribed by NCVT or SSC.
9	Candidate enrolment	Not verified leading to large-scale bogus enrolments; weak inspection and monitoring leading to rampant fraudulent practices	Aadhaar-backed biometric attendance with CCTV monitoring and recordings periodically reviewed
10	Training sessions	Not defined; no standards; no quality parameters	As per NCVT/SSC norms together with mandatory DDU-GKY modules – soft skills, IT training, and English communication. Increased focus on quality outcomes defined by industry with on-the-job training (OJT) component.

11	Assessment & certification	Proposed by PIAs themselves in complete violation of mandatory third-party assessment criteria, by and large bogus, no industry or government recognition, sometimes undertaken by own subsidiary, often no assessments undertaken	Well-regulated third-party assessors appointed by RDAT or SSC. Candidates receive industry validated, government-recognised certificates compliant with NSQF
12	Jobs	Weak placement verification process, bogus placements, gross violation of minimum wage, placements, if any, predominantly in unskilled / semi-skilled job roles, no clear placement criteria. High attrition jobs and career stagnation leading to high levels of dropouts	Well-defined placement criteria, compliant with minimum wage norms together with PF and ESI. Placement incentives to promote employment in right jobs with career progression and low attrition
13	Scale	Unscalable model with only a few hand-picked implementing agencies identified based on rapport rather than capacity & credibility	Implementing agencies selected through a formal EoI and quality / technical selection process. Scale increased 100-fold with much higher programme quality and programme integrity
14	Overseas Jobs	None whatsoever	Top priority with special incentives
15	People with disability (PwD)	Unstructured and compromised to a great extent. No special provisions for PwDs which was part of the existing programme	Separate programme norms and increased budgets with special focus on PwD's needs like disabled-friendly infrastructure and trades across sectors identified and categorized for PwDs
16	Public awareness and industry reach out	Literally non-existent	Effective outreach through formal IEC and nationwide branding through print and electronic media and social networking
17	Industry relevance	No policy/ weak programmatic response. LoIs irrelevant and even bogus / forged	Robust and strong policy focus on industry participation. QP/NOS (job roles) validated by at least 30 industries across large, medium and small sectors. Jobs in industries verified during quality appraisal before project sanction. Syllabus and training content validation by industry. Mandatory guest lectures and industry visits during training. Strong OJT component. State government also conducts job fairs and MoRD has a strong and robust industry partnership policy led by a dedicated cell with DDU-GKY

Yet another instance where the Congress party failed to create aspirational jobs was under the SGSY-Special Projects wherein the programme was found wanting in quite a number of other ways as well:

Programmes like the NSDC, Star Scheme and SGSY-SP are implemented by the government to create 'relevant jobs'. Data, going back some 10 years, pertaining to job creation, is available for all to see and one will be able to see how many relevant jobs the Congress party has provided to India's aspirational youth. Unlike the Mudra Yojana, these were government efforts to secure 'jobs' not 'self-employment'. Therefore, a discussion on the outcomes of these programmes will reveal which government has actually worked towards securing 'jobs'.

The Rural Skills Programme in its current form as Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (DDU-GKY) is a far superior programme in every aspect when compared to the SGSY-Special Projects. During the UPA I and

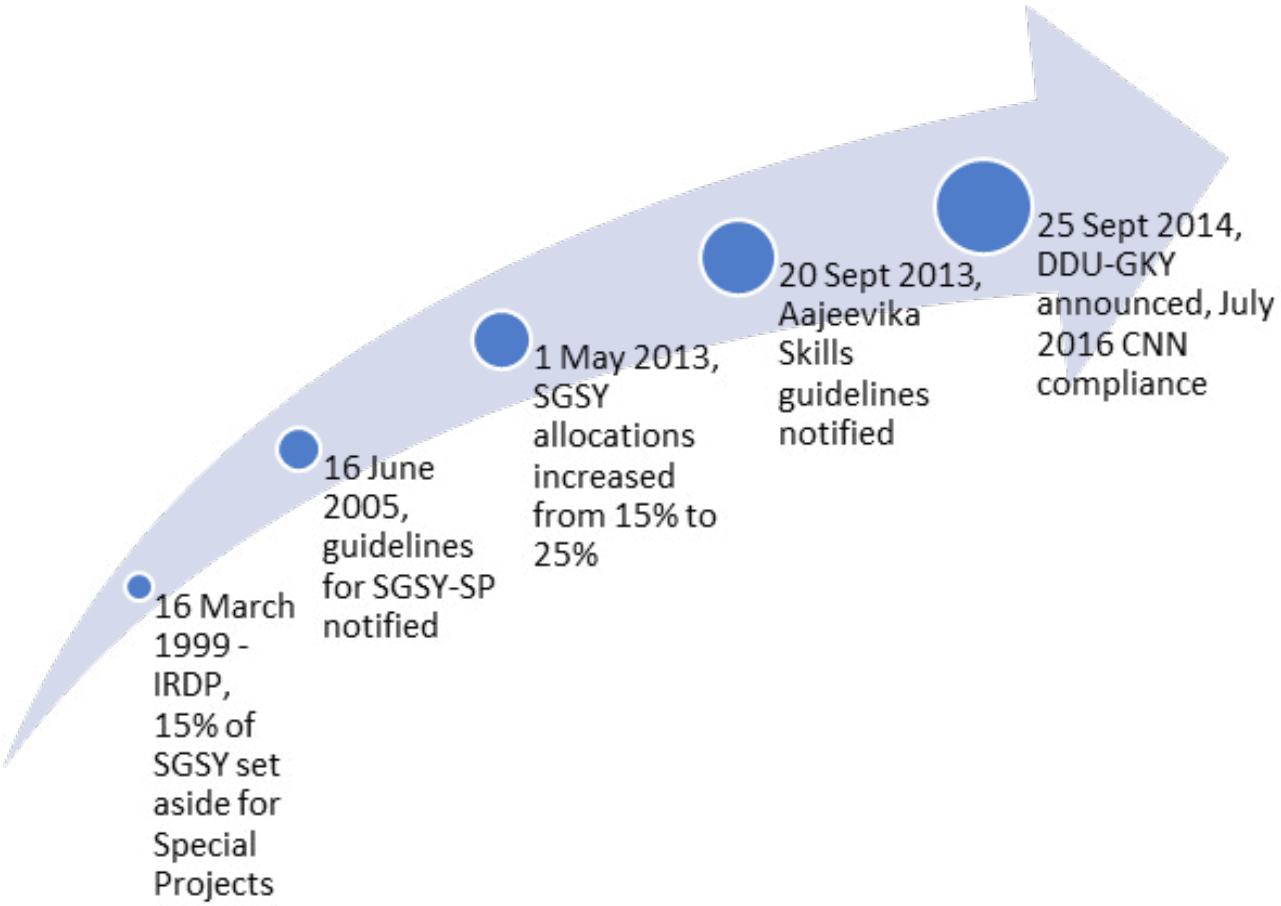

II rule, SGSY-Special Projects reported having organised very many unverified if not bogus training programmes and provided placements. Jobs, if any, were generated only in the unskilled or semi-skilled category requiring little or no skilling intervention. According to the ILO, programmes such as the SGSY–Special Projects are market insertion programmes as these cater to the unskilled and semi-skilled jobs market that require little skilling.

With a presence in just three of the thirty states, a bare minimum representation in the Lok Sabha, and an ever-declining representation in the Rajya Sabha, the Congress party is indeed faced with an existential crisis. But even if it manages to sort out its existential crisis, it still needs to deal with an 'identity issue' crisis. The Congress party is no longer engaged with issues that really matter to the people. Its stubborn refusal to break free from the 'Congress Culture' has alienated it from the people. It certainly is the responsibility of the Congress party as the main opposition party in parliament to perform its constitutional duties but spewing a host of lies on the nation undermines the very foundations of democracy that the BJP has sworn itself to safeguard.

(The author is Founder and CEO, Policy Matters Institute (a New Delhi based Economic and Public Policy Advisory Organization). The views and opinions expressed in this article are those of the authors and do not necessarily reflect the official position of SPMRF.)

आर्थिक मोर्चे पर 4 साल की मोदी सरकार का लेखा-जोखा

हर्षवर्धन त्रिपाठी

कड़े फैसलों, आर्थिक सुधार, मजबूत बुनियाद पर बनती अर्थव्यवस्था की मजबूत इमारत, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बन गई है। देश की तरक्की की रफ्तार के इन आंकड़ों की उम्मीद कम ही लोगों को रही होगी। सरकार ने पिछले 4 साल में जिस तरह के फैसले लिए, उससे अर्थव्यवस्था में धीरे-धीरे अच्छी तेजी की उम्मीद सभी लोगों को थी। लेकिन, अर्थशास्त्रियों का बड़ा वर्ग जिस तरह से नोटबन्दी और जीएसटी की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को लड़खड़ाते देख रहा था, वैसा नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की सरकार के 4 साल पूरे हो चुके हैं। वैसे तो किसी भी चुनी हुई सरकार के लिए हिसाब देने का वक्त 5वें साल में होता है। लेकिन, सच यही है कि, चौथे साल के रिकॉर्ड से ही, करीब साल भर बाद होने वाले चुनावों में जनता फैसला लेगी। और, यह भी सही है कि पांचवें साल में सरकार अगले 5 साल के लिए चुनाव की नजर से काम करना शुरू कर देती है। उसमें नई योजनाओं को लागू करना होता है। इसीलिए उस पर बात करना आर्थिक नजरिए से सही नहीं होगा। इसीलिए हम उन योजनाओं और आर्थिक आंकड़ों की ही बात करेंगे, जो चौथे साल में स्पष्ट नजर आ रहे हैं। ताजा आंकड़ा है 2017-18 के तरक्की की रफ्तार के आंकड़े। 2017-18 की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च में भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की की रफ्तार 7.7% रही है। पूरे साल की तरक्की की रफ्तार 6.7% रही है जो, पिछले साल के 7.1% से कम है। लेकिन, बीते वित्तीय वर्ष की आखिरी तिमाही के आंकड़ों को सन्दर्भ के साथ देखने पर भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूत बुनियाद पर मजबूती से तैयार होती इमारत दिखने लगती है।

एशियाई विकास बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री यासुवुकी सावादा का कहा- भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर नरेंद्र मोदी

सरकार के 4 साल के कामों को बयान करता है। उन्होंने कहाकि, 2018-19 के लिए भारत की अनुमानित 7 प्रतिशत से ज्यादा की तरक्की की रफ्तार आश्चर्यजनक रूप से तेज है। जबकि, एशियाई विकास बैंक के मुताबिक, 2018-19 में 7.3% और 2019-20 7.6% की विकास दर का अनुमान है। रिपोर्ट में कहा गया है कि, भारत की 8% तरक्की की रफ्तार के पीछे भागने के बजाय आय असमानता पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि, विकास दर को निर्यात से ज्यादा घरेलू खपत से मदद मिलती है। यहां एक बात समझने की है कि, निर्यात से कुछ लोगों को रोजगार और कम्पनियों का बही-खाता बेहतर होने से जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े बेहतर दिख सकते हैं। लेकिन, घरेलू खपत से ही अर्थव्यवस्था की असली तेजी समझ आती है। इससे देश में लोगों की खर्च करने की क्षमता और आय असमानता की कमी का भी पता चलता है। माना जा रहा है कि ढाई लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की भारतीय अर्थव्यवस्था 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की हो सकती है। 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था को दोगुना करने के लिए पिछले 4 सालों में नरेंद्र मोदी सरकार ने क्या किया है।

खनन को छोड़कर सभी प्रमुख क्षेत्रों में तरक्की की रफ्तार अच्छी रही है। 2017-18 की चौथी तिमाही के आंकड़ों की तुलना करें तो, मैन्यूफैक्चरिंग की तरक्की की रफ्तार 9.1% रही है जो पिछले साल 6.1% थी। बिजली, गैस और जल आपूर्ति जैसी बेहद जरूरी सुविधा की बात करें तो तरक्की की रफ्तार पिछले साल के 8.1% के मुकाबिल 7.7% बनी हुई है। नोटबन्दी की वजह से सबसे बुरा असर रियल एस्टेट क्षेत्र पर हुआ था। क्योंकि, सबसे ज्यादा काली कमाई बिल्डरों ने ही लगा रखी थी। अब इसमें भारी कमी आई है, जिससे रियल एस्टेट क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और उसी का असर है कि, चौथी तिमाही में इस साल कंस्ट्रक्शन सेक्टर 11.5% की रफ्तार से बढ़ा है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में रियल एस्टेट बढ़ने के बजाय 3.5% घट गया था। नोटबन्दी और रियल एस्टेट रेगुलेशन कानून से लोगों को अब सस्ता घर मिल पा रहा है। घरों की कीमत में 35% तक की कमी आई है। हालांकि, काले धन के आधार पर खड़े बिल्डरों के दिवालिया होने से परेशान ग्राहकों के मद्देनज़र इस रेगुलेशन में और पेंच कसा जाना आवश्यक है। सेवा क्षेत्र में भी अच्छी बढ़त देखने को मिली है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार जब कड़े फैसले ले रही थी, उस समय निजी क्षेत्र ने निवेश की रफ्तार घटा दी थी। निजी क्षेत्र को मोदी सरकार से इस तरह के कड़े फैसलों की उम्मीद भी नहीं रही होगी। इसीलिए निजी क्षेत्र के हाथ बांधने के दौरान सरकारी खर्च तेजी से बढ़ा। रियल एस्टेट क्षेत्र में जब मंदी की बात की जा रही थी, उसी दौरान सरकार

ने गांवों और शहरों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1 करोड़ घर बनाकर तैयार कर दिए। उज्ज्वला योजना के तहत 3.8 करोड़ से ज्यादा घरों में रसोई गैस कनेक्शन दे दिया गया है। आर्थिक मोर्चे पर हुए इन कामों को सरकारी काम कहकर अर्थशास्त्री किनारे कर देते हैं। लेकिन, सामाजिक योजना के साथ आर्थिक तरक्की का काम बड़े सलीके से मोदी सरकार ने किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार के 4 सालों का आर्थिक हिसाब लगाते वक्त एक और बेहद जरूरी आंकड़ा ध्यान में रखना जरूरी है। वो आंकड़ा है, सीधे खाते में जरूरतमंदों को मिलने वाली रकम का, जिसे सरकार डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर कहती है। 2014-15 से 2017-18 तक करीब 4 लाख करोड़ रुपए सीधे लोगों को खाते में चले गए। एशियाई विकास बैंक जिस घरेलू खपत को बढ़ाने और आय की असमानता को कम करने की बात कह रहा है, उस लिहाज से ऊपर के तीनों आंकड़े भरोसा पैदा करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किस तरह से भारत में परिवहन का तरीका बदल रहा है, साफ दिख रहा है। 2013-14 में सड़क निर्माण पर सरकार ने 32483 करोड़ रुपए खर्च किए और 2017-18 में सरकार ने 116324 करोड़ रुपए खर्च किए और इसका परिणाम रहा कि 2013-14 में 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़के बनाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आज

27 किलोमीटर प्रतिदिन राजमार्ग बना रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के लोगों ने प्रदूषण और जाम पर ढेरों शेखचिल्ली फैसले झेले हैं। अब ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे और सराय काले खां से यूपी गेट तक 14 लेन की सड़क देखकर उन्हें समझ आ रहा होगा कि बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए बड़े फैसलों को अमल में लाने की जरूरत होती है।

नोटबन्दी और जीएसटी ये ऐसे कड़े और बेहद जरूरी सुधार रहे हैं, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गई है। यह भी सही है कि, आर्थिक पारदर्शिता और मजबूती के लिए इतने बड़े प्रयास एक साथ कभी नहीं हुए, जितने इन 4 सालों में हुए हैं। आयकरदाताओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि इसी का परिणाम कहा जा रहा है। सिर्फ आयकरदाताओं की संख्या में ही वृद्धि नहीं हुई है, आयकर चोरी और आर्थिक अपराध के मामलों में तेजी से सरकार ने कार्रवाई की है।इसे और आसानी से इस तरह से समझा जा सकता है कि सूट-बूट की सरकार का आरोप लगाता विपक्ष अब उद्योगपतियों पर टैक्स टेररिज्म की बात करने लगता है। और, जिन उद्योगपतियों ने मोदी सरकार के राज में आसानी से सरकारी योजनाएं अपने पक्ष में कर लेने की उम्मीद की थी, वे निराश हो रहे हैं।गुजराती कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की सम्पत्तियों को जब्त करने के साथ ही जिस तेजी से आर्थिक अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, अभूतपूर्व है। गुजरात के संदेसरा समूह की 4700 करोड़ रुपए की सम्पत्ति हाल ही मेंजब्त की गई है। कानपुर के रोटोमैक के मालिक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किए गए।आर्थिक अपराधों के मामले में मोदी सरकार की लगातार कार्रवाई ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सूट-बूट की सरकार के आरोप का प्रभाव लगभग शून्य कर दिया है।यूपीए सरकार में उद्योग संगठन और दूसरे सत्ता के दलाल प्रभावी थे, उनका दिल्ली के पावर कॉरीडोर में महत्व ही खत्म हो गया है। उद्योग संगठन कह रहे हैं कि लॉबी नहीं कर पा रहे हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था की बात बिना कृषि के अपूर्ण है। खासकर ऐसे समय में जब देशभर में किसान आन्दोलन खड़े होते दिख रहे हैं या राजनीतिक तौर पर खड़े किए जा रहे हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि खेती के लिए सरकार क्या कर रही है और उसका कितना असर जमीन पर दिख रहा है। किसी किसान नेता ने किसानों को शायद ही यह बात समझाने की कोशिश की हो कि कैसे 1 लाख 71 हजार किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कें पिछले 4 साल में बनने से किसानों के जीवन में और उपज बेचने में आसानी आई है। 2013-14 में हर दिन 60 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनती थीं, पिछले 4 सालों में यह रफ्तार 134 किलोमीटर प्रतिदिन है।1 लाख 16 हजार ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचने से किसानों तक सूचनाएं आसानी से पहुंच रही हैं और राष्ट्रीय कृषि बाजार योजना के 585 मंडियों में लागू होने से किसान अपनी ग्राम पंचायत से बैठकर ही उपज का भाव जान सकता है। कमाल की बात यह भी है कि किसानों ने नए सिरे से जिस आन्दोलन को लागत का डेढ़ गुना ज्यादा कीमत देने की बुनियाद पर शुरू किया है, उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार पहले से ही ढेरों कोशिशें करती दिख रही है। इसके नतीजे भी अच्छे दिख रहे हैं। कृषि क्षेत्र की विकास दर 4.5% रही है। अच्छी बात यह है कि इस साल भी अच्छी बारिश के अनुमान से खेती बेहतर होती दिख रही है और किसानों की बढ़ती उपज का दबाव है कि सरकार ने रिकॉर्ड सरकारी खरीद की है। पहली बार किसी सरकार ने दाल का इतना बड़ा भंडार तैयार किया है।4 साल में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड सरकारी खरीद और किसानों के लिए ढेर सारी अच्छी योजनाओं के लागू होने का नतीजा है कि 2017-18 में रिकॉर्ड पैदावार हुई है। कुल अनाज की पैदावार 27 करोड़ 75 लाख टन की रही है। 11 करोड़ टन से ज्यादा धान की पैदावार हुई और मोदी सरकार में दालों की कमी से जूझते भारत में दालों की पैदावार 2 करोड़ 40 लाख टन की रही। गन्ना, फल-सब्जियों और मोटे अनाज में भी रिकॉर्ड बढ़त देखने को मिली।

विपक्ष हमेशा मोदी सरकार की आलोचना करता है कि मेक इन इंडिया से लेकर डिजिटल इंडिया सिर्फ योजनाओं का नाम भर रहा, जमीन पर कुछ देखने को नहीं मिला। मेक इन इंडिया का बेहतर परिणाम समझने के लिए इस आंकड़ों को जरूर जानना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई थी तो, भारत में मोबाइल बनाने की सिर्फ 2 इकाईयां थीं, आज देश में 120 मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग इकाईयां लगी हुई हैं। 6 करोड़ से बढ़कर भारत आज 22 करोड़ 50 लाख मोबाइल हैंडसेट बना रहा है। अगर इनकी कीमत जानना चाहें तो 1 लाख 32 हजार करोड़ रुपए के मोबाइल का उत्पादन भारत में हो रहा है। 4 साल की मोदी सरकार को आर्थिक पैमाने पर आंकें तो नीति विकलांगता और भरोसे का संकट झेल रही भ्रष्टाचारी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगातार फैसले लेने पड़े हैं। जिसकी वजह से कई बार अर्थव्यवस्था को झटके भी झेलने पड़े हैं। लेकिन, पांचवें साल में सरकार के कड़े और श्रृंखलाबद्ध आर्थिक फैसलों का बेहतर असर दिखने लगा है।

(लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुख़र्जी रिसर्च फाउंडेशन में सीनियर फेलो है ।)

How NDA Government Schemes Have Helped the Poorest of the Poor

Ananth Krishna

The schemes and programmes of the second National Democratic Alliance Government led by PM Narendra Modi have been oriented towards the poorest of the poor, in order to bring to the mainstream of Indian society. This article will focus on how the schemes of the Union Government have bought electricity to the homes of millions and bought banking facilities to those thus far neglected by the banking sector.

Electrification

The Prime Minister promised in his 2015 Independence Day address to electrify the 18,000 odd villages that were still in darkness after 68 years of independence. True to his word, the government declared on 28th April 2018 that all of the 18,452 villages had been electrified. One must underestimate the magnitude of this achievement. The fact that these villages were living in darkness so many years speaks to the nature of the earlier

government's priorities compared to the current government. The Narendra Modi government introduced the "DeenDayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana" (DDUGJY) to provide 24x7 Affordable, reliable and adequate power for all. This scheme has been undertaken under the principle of 'Antyodaya', literally 'the rise of the last person'. This government's philosophy is the commitment to improve the lives of those at the lowest strata of society, and the same is reflected in the implementation of this scheme.

The challenges to the implementation of total electrification should not be gleamed over. Firstly, there were geographical challenges – river crossings, treacherous mountain passes and rocky terrain. Added to this was the problem of villages situated in districts affected by Left-Wing Extremism (LWE). Around 7,000 unelectrified villages were in these LWE-affected districts. To overcome these challenges requires drive and spirit that this government infused into the scheme.

Detractors of the Modi government would be quick to point out that the NDA Government electrified only 18,000 villages, compared to 1 lakh under the two term United Progressive Alliance (UPA) Government. What needs to be remembered at this point is not only that the above mentioned challenges to electrification, but also certain statistics. In 2012-13, 2587 villages where electrified. In 2013-14, it was 1197 and in 2014-15 it was 1405, After the launch of DDUGJY, 7,000 villages were electrified in 2016-17 alone.

The momentous achievement of the Modi Government has not gone unnoticed internationally. Middle East and African countries have expressed interest in engaging Rural Electrification Corporation in the role of a consultant or financing and technology transfer.

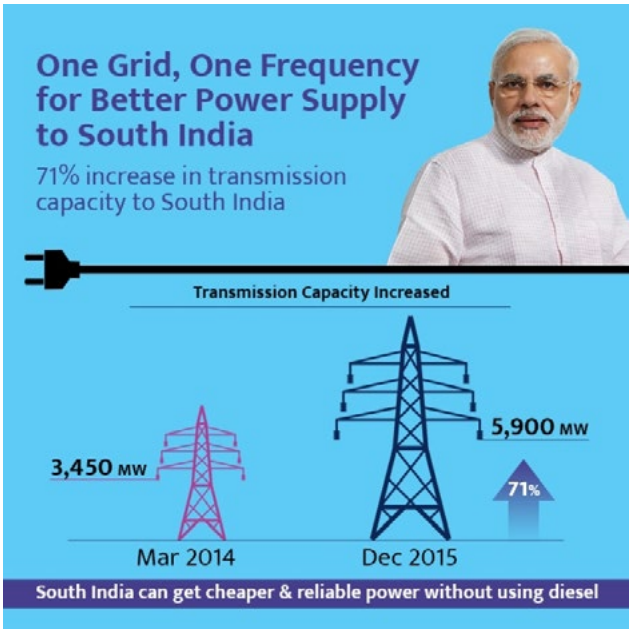

The Central government is however not resting in the laurels – it has already set its sights on electrifying every single household in the country under the 'SAUBHAGYA' scheme. This was launched in September 2017, and provides free electricity connections to all households. This means that there will be no discrimination in implementing this scheme for households below or above the poverty line. The aim is to electrify every single household by December 2018. The task if achieved, will be unparalleled. Around 4 crore households are yet to experience electricity. The scheme has already bought lights to half a crore households, and the pace is sure to increase in the coming months.

These schemes are aimed at the on-ground change in electricity distribution. This does not mean that the Modi Government has neglected the general health of the energy sector. In fact under the leadership of Shri Piyush Goyal, the Former Minister for power and currently by Sri. R.K. Singh, India became a Power Surplus country. However, the Transmission and

Distribution systems in the country have been below par. This problem was compounded by the failing financial health of Power Distribution Companies at the state level. The Union Government therefore initiated the Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY) for the financial turnaround of these companies.

An 'Open' Government

Another Important feature of the schemes that the central government has initiated is the transparency in the implementation of the schemes. The power ministry made available the details of the implementation of all its schemes online in detail. This means that the citizen can see data regarding the success of the electrification drive, real time. This is undoubtedly a revolutionary change from the 'closeted' nature of previous administrations. This break represents a change for the better. This information was made available under the GARV app on Android/Apple Platforms as well. The app facilitates interaction between citizens and the Implementation agencies, a one of a kind initiative for participatory governance.

Financial Inclusion

The Narendra Modi Government has not limited itself to the emphasis on infrastructure development in rural areas. The government has initiated the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) to promote Financial Inclusion, which is the process of ensuring access to financial services to weaker sections and low income groups at an affordable cost. In other words, it is the universal access to a wide range of financial services at a reasonable cost.

The Jan Dhan Yojana was launched by the Prime minister on 28 August 2014, the scheme aims to provide at least one account for one household has been immensely successful. As of 09th May 2018, the total number of beneficiaries for the scheme are 31 crore and the deposits in these accounts have reached ₹81,000 crore. A unique fact regarding the implementation of the scheme has been that the majority of the beneficiaries under the scheme are women. There is no minimum balance requirement for the bank accounts opened under this scheme, and the account can be used by beneficiaries of Government to avail Direct Benefit Transfer. To promote accessibility to banking facilities, the government has given further impetus to 'Bank Mitr', agents of Public sector banks who are to visit villages where banking facilities are not available on fixed days. An overdraft facility of ₹5,000 is provided for accounts 6 months after account opening. With an eye to provide 21st century banking facilities to weaker sections of society, 16 crore RuPay debit cards have been issued to beneficiaries of the Jan Dhan Yojana. Mention has to be made at this point about Unified Payment Interface (UPI) a payment interface developed by the National Payments Corporation of India and the Bharat Interface for Money app (BHIM, named after the great B.R. Ambedkar), which is facilitating a cashless revolution in India. Using UPI, the National Payments Corporation is also providing offline

access to bank accounts as well. The potential for this application and the change it can bring about is apparent. And so far, we can see that the initiative has been successful. There was 14.5 crore transactions that utilised UPI just in month of December 2017, and this number is only set to rise even further.

The Government has not restricted itself to schemes that benefit the end-consumer. Taking a holistic view of the banking sector, the government has initiated the first step to the consolidation of Public Sector Banks with the merger of State Bank of India with its five associate banks in October 2017. Moreover, the Union Government has announced that it will be infusing ₹2.11 trillion capital into public sector banks. This is intended for the banks to expand credit, earn interest and grow balance sheets so that they can be harbingers of economic activity.

Conclusion

The NDA Government led by PM Narendra Modi has proven beyond doubt that it is committed to the upliftment of the weakest sections of society.The government has taken comprehensive action not only to secure benefits to the common man, but has simultaneously strengthened the underlying institutions. The manifesto of the BJP for the 2014 General elections promised to ensure electricity for all , and to ensure financial inclusion. As of 2018, this government has substantially achieved both. 99% of Households in the country now have at least one bank account, and 100% of villages have been electrified. The magnitude of these achievements speaks for itself.

(Ananth Krishna is currently a Third Year BA LLB(Hons.) student at The National University of Advanced Legal Studies, Kochi. He blogs at http://chhitblog.wordpress.com)

National Health Policy, 2017: A Paradigm Shift Towards Making India Healthy

Madhura Joshi

Every person desires for an innocuous life free from any major diseases and every responsible government endeavors to provide its citizens with the best facilities in order to assist them. National Health Policy (2017) can be considered as yet another propitious scheme by Modi Government, attempted towards the dream of a Healthy India.

Although the prior two Healthcare Policies of 1983 and 2002 had brought in major progress in Health Care Industry, the 14 year gap required a new revised policy as over the years many changes have taken place in the Health Care Milieu such as despite decline in Infant Mortality and Maternal Mortality Rate, many communicable and infectious diseases have seen a distend. National Health Care Policy (2017) has the potential to become a benchmark of all the Healthcare Policies implemented further. NHP, 2017 aims to fortify and compute the role of Government in the Health Sector to attune various dimensions such as investments, promotion of schemes, expenditure etc. NHP (2017) covets to provide exemplary healthcare services to people of all sections of the society, of all ages at a very affordable price. It can be seen

as yet another efficacious ascend towards Prime Minister Modi's motto of 'SabkaSaath, Sabka Vikas'.

The Policy aims to adhere to the principles of Professionalism, Integrity and Ethics along with Equity to be compelling to all members of society, Affordable to be effective among all classes, Universality to be impartial to all, Patient Centered and Qualitative to be efficient among the people, Decentralized to be efficient and Dynamic and Adaptive to keep up with constant changes in flourishing health industry. Impact of this scheme would be enormous as it has aimed to encompass all the sections of society and will be proved very efficient in coming future. Following are the expected impacts:

The policy advocates a progressively incremental assurance based approach. It envisages providing larger package of comprehensive primary health care through the 'Health and Wellness Centers' and denotes important change from very selective to comprehensive primary health care package which includes care for major NCDs, mental health, geriatric health care, palliative care services.

It aspires to allocate major chunk of available wherewithal to the primary health services and intends to ensure availability of two beds per thousand populations distributed in a manner that the victim gets access to it at golden hour.

The decision of strengthening healthcare systems can be considered as another illustrious step in the overall buildup of the systems. It includes increase in Health Expenditure from 1.5% of the existing GDP to 2.5% by 2025, ensuring availability of paramedics and doctors as per IPHS standard, ensuring district level electronic database of information on health system components by 2020. The Digitization of Health care systems is possible due to the efficacious 'Digital India' campaign of Prime Minister Modi, which has brought in tremendous changes.

For Healthy body, a major expedient is a healthy environment, which was so far neglected in previous health policies. The Policy is now developed with 'Health for all' inclusive in 'Health to all'. The prominent stress on development of an innocuous environment is a copacetic vision of Mr. Prime Minister. The Policy identifies following improvable areas for overall amelioration of Environment and Health:

1. Swaccha Bharat Abhiyan
2. Balanced Diets and Regular Exercises
3. Addressing Alcohol, Drugs and substance use
4. Prevention of Deaths due to Road and Rail Accidents (Yatri Suraksha Abhiyan)
5. Action against Gender Violence (Nirbhaya Nari)
6. Stress Management
7. Control of Pollution

The interdependence of all the policies in here is a prominent decision, as it will ensure each and every policy works properly. This will also compel the policy enablers to act vigilantly due to the importance of contribution of each one of them.

Another laudable aspect of NHP (2017) is that it focuses on impartment of knowledge

regarding health care right from childhood. The current government has put a lot of emphasis for investment on School Health that includes hygiene education, promoting self-care systems in School Environment taking in AYUSH policy for promotion of Yoga and Ayurveda within the school place, is designed to promote Health Care based on Indic Knowledge. This can be counted as a really promising and efficacious step in reviving the rich ancient Indian tradition of fitness that will be here to stay in coming years.

The Policy aims at improving and giving special focus on Primary Health Care package which includes geriatric, palliative and rehabilitative services. The facilities start with providing each and every family a health card which will be linked to health institutions through which they can avail facilities anywhere in India.

Secondary care aims to provide services at district health care centers which were first being provided in medical college hospital such as caesarian section, neonatal care etc.

Tertiary Health Care services focus on co-ordination between urban-district and zonal regions. It also envisages on opening of new AIIMS hospitals andnew medical colleges in the country.

NHP(2017) also covers implementation of various national programs like Child and Adolescent Health, Addressing of Malnutrition, Universal Immunization, Prevention of communicable diseases, Control of TB, Control of HIV/AIDS, Leprosy Elimination, Vector-Borne Disease Control, Mental Health and population stabilization.

As far as a Policy Success is concerned, only paramount design is not enough, on-ground implementation prototype plays a vital role in the overall success of the policy. Implementation of NHP is bound to success due its structural framework. NHP Stresses on accountability of Centre and States regarding Policy Implementation. It also stresses on Resource based allocation, strengthening of institutional mechanisms and coordinated implementation as way forward. Fiduciary risks, provision of capacity building, technical assistance to states to develop their own strategic plans, through involvement of local self-governments are also included. Panchayats Raj Institutions are also being strengthened to play active role in the implementation.

NHP(2017) cogitates to bring in prominent revolutionary changes in the Health Care industry and to provide basic health-care systems to all with minimal cause, providing hygienic environment at the same time. It can be viewed as a monumental attempt at co-development and co-existence of humans and the environment around us.

(Madhura Joshi is a student of Engineering at the University of Mumbai and a regular columnist on social and economic issues.)

आर्थिक मजबूती, पारदर्शी शासन और कल्याणकारी नीतियों के चार वर्ष!

सतीश सिंह

विगत चार सालों में मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिये अनेक कदम उठाये हैं। देखा जाये तो मोदी सरकार द्वारा किये गये विकासात्मक कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त है। नवंबर, 2016 में विमुद्रीकरण करने का निर्णय लेना मोदी सरकार द्वारा उठाया गया एक साहसिक कदम था। इस निर्णय से नकसलवाद, आतंकवाद, कालेधन एवं कर चोरी पर रोक तो लगी ही, साथ ही डिजिटलीकरण को भी बढ़ावा मिला। इसके बाद सब्जी वाले, खोमचे वाले, चाय वाले आदि भी डिजिटल लेनदेन करने लगे। इतना ही नहीं बड़े-बुजुर्ग और ग्रामीण महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर डिजिटल लेनदेन में हिस्सा लिया।

जीएसटी से अर्थव्यवस्था को मजबूती

अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिये विमुद्रीकरण के तुरंत बाद जीएसटी को लागू किया गया। यह एक सशक्त अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है। जीएसटी के तहत अलग-अलग कर की बजाय एक कर का प्रावधान किया गया। इससे विनिर्माण लागत में कमी आई। उपभोक्ताओं को आज देश भर में किसी भी सामान या सेवा का एक शुल्क अदा करना पड़ रहा है। टीवी, गाड़ी, फ्रिज एक ही कीमत पर मुंबई, दिल्ली, पटना, भोपाल आदि शहरों में उपभोक्ताओं को मिल रहा है।

इससे कर चोरी की वारदातें एवं कर विवाद के मामले कम हो रहे हैं। टैक्स वसूली की लागत में भी उल्लेखनीय कमी आई है। रोजगार सृजन में वृद्धि, चाइनीज उत्पादों की बिक्री में कमी, जरूरी चीजों पर कर कम होने एवं विलासिता की वस्तुएं महँगी होने से सरकार व आम लोगों दोनों को फायदा हो रहा है।

एक अनुमान के मुताबिक अप्रत्यक्ष कर की इस नई व्यवस्था से अर्थव्यवस्था को 60 लाख करोड़ रुपये का फायदा होने का अनुमान है, जिससे सरकार रोजगार सृजन, आधारभूत संरचना का विकास, औद्योगिक विकास को गति, अर्थव्यवस्था को

मजबूत आदि करने में समर्थ हो सकेगी। इससे लाजिस्टिक लागत में भी कमी आयेगी। इस नई कर प्रणाली से देश के विकास दर में लगभग दो प्रतिशत तक का इजाफा होने का अनुमान है।

भ्रष्टाचार में कमी

भ्रष्टाचार को विकास की राह में सबसे बड़ा रोड़ा माना जा सकता है। बढ़ते वैश्वीकरण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वित्तीय लेनदेन में भ्रष्टाचार की गूँज साफ तौर पर सुनाई देती है। आज कोई भी ऐसा देश नहीं है, जो अपने यहाँ इसकी उपस्थिति से इंकार कर सके। देखा गया है कि भ्रष्टाचार का प्रतिकूल प्रभाव निर्णय लेने की क्षमता और प्राथमिकताओं के चयन पर भी पड़ता है।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा वर्ष 2016 में प्राप्त कुल शिकायतों में से बाहरी शिकायतें केवल 0.17% ही थीं, जो इस बात का संकेत है कि पहले की तुलना में प्रशासन ज्यादा साफ-सुथरा हुआ है। ई-निविदा, ई-खरीद, रिवर्स नीलामी आदि कार्यों के नवीन प्रौद्योगिकी के जरिये होने से शासन एवं उसकी कार्यविधियों में पारदर्शिता आई है।

निवेश, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश सहित, प्रतिस्पर्धा, उद्यमिता, सरकारी व्यय, राजस्व आदि पर भ्रष्टाचार का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2011 से वर्ष 2016 के दौरान भारत, ब्रिटेन, पुर्तगाल एवं इटली जैसे देश भ्रष्टाचार की धारणा सूचकांक (प्रति वर्ष पारदर्शिता इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित) में समग्र रूप से श्रेणी उन्नयन करने में सफल रहे हैं। दूसरी तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था में गिरावट के दौर में भी भारत सकारात्मक जीडीपी दर हासिल करने में सफल रहा है।

भारत वर्ष 2011 के 95 वें श्रेणी में सुधार करते हुए वर्ष 2016 में 79 वें स्थान पर आ गया। भारत में भ्रष्टाचार के स्तर में सुधार आने से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के प्रवाह में भी तेजी आई है। आंकड़ों से पता चलता है कि भारत के प्रति विदेशी निवेशकों का भरोसा पहले की तुलना में बढ़ा है। भारत में शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रवाह पिछले छह सालों यथा, वित्त वर्ष 2012 के 21.9 यूएस बिलियन डॉलर से बढ़कर वित्त वर्ष 2017 में 35.9 यूएस बिलियन डॉलर हो गया, जो प्रतिशत में 64 है।

सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था

भारत पिछले तीन सालों से सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना हुआ है। मुद्रास्फीति वर्ष 2014 से लगातार नीचे आ रही है और चालू वित्त वर्ष में भी यह चार प्रतिशत से ऊपर नहीं जायेगी। इस वित्त वर्ष में चालू खाते का घाटा दो प्रतिशत से कम होगा और विदेशी मुद्रा भंडार 400 अरब डॉलर से अधिक हो चुका है।

राजकोषीय घाटे को चालू वित्त वर्ष में जीडीपी के 3.2 प्रतिशत के लक्ष्य के दायरे में रखने के लिये लगातार कोशिश कर रही है। औद्योगिक एवं कारोबारी गतिविधियों में तेजी लाने के लिये सरकार सरकारी खर्च में इजाफा कर रही है। केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने 3.85 लाख करोड़ रुपये के उनके व्यय लक्ष्य से 1.37 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च किये हैं। अगले पांच साल के दौरान 83,677 किलोमीटर सड़क निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार लाने के लिए सरकार ने "इंद्रधनुष" नाम से एक सात आयामी योजना शुरू की है, जिसमें नियुक्तियां, बोर्ड ऑफ ब्यूरो, पूँजीकरण, तनावमुक्त माहौल का सृजन, सशक्तिकरण, जवाबदेही के ढांचे का निर्माण एवं सुशासन जैसे सुधारात्मक पहल शामिल हैं। इसके तहत सरकार4 साल की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी मुहैया करायेगी।

भारतीय रिजर्व बैंक और कुछअन्य एजेंसियों के अनुसार बेसल III के कार्यान्वयन के बाद बैंकिंग क्षेत्र को लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कामकाज में सुधार लाने के लिए सरकार ने "इंद्रधनुष" नाम से एक सात आयामी योजना शुरू की है, जिसमें नियुक्तियां, बोर्ड ऑफ ब्यूरो, पूँजीकरण, तनावमुक्त माहौल का सृजन, सशक्तिकरण, जवाबदेही के ढांचे का निर्माण एवं सुशासन जैसे सुधारात्मक पहल शामिल हैं। इसके तहत सरकार4 साल की अवधि में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पूँजी मुहैया करायेगी।

लिहाजा, सरकार बैंकिंग क्षेत्र में 2.11 लाख करोड़ रूपये का पुनर्पूंजीकरण कर रही है, जिसमें बजट के माध्यम से बैंकों को 18,139 करोड़ रूपये दिया जायेगा। 1.35 लाख करोड़ रूपये का पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी किया जायेगा और बची हुई राशि की व्यवस्था बैंकों में सरकारी हिस्सेदारी को कम करके एवं बाजार से जुटाया जायेगा, ताकि बैंक वैश्विक पूंजी पर्याप्तता एवं बासेल तृतीय के मापदण्डों का पूरी तरह से अनुपालन कर सकें।

अन्य विकासपरक और लोक कल्याणकारी नीतियां

देश में से अंधेरा भगाने के लिये अक्षय ऊर्जा के दोहन के लिये प्रयास किये जा रहे हैं। अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र को व्यापक और प्रभावी बनाने के लिए "नवीन एवं अक्षय ऊर्जा" के नाम से एक स्वतंत्र मंत्रालय बनाया गया है। भारत विश्व का पहला देश है, जहाँ अक्षय ऊर्जा के विकास के लिए एक अलग मंत्रालय है। बजट में अक्षय ऊर्जा की क्षमता को 2022 तक 1,75,000 मेगावाट बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। 1,75,000 मेगावाट में सौर ऊर्जा का हिस्सा 1,00,000 मेगावाट, पवन ऊर्जा का हिस्सा 60,000 मेगावाट, जैव ईंधन का हिस्सा 10,000 मेगावाट और जल ऊर्जा का हिस्सा 5,000 मेगावाट रहेगा।

सरकार ने वित्त वर्ष, 2019 के बजट में "आयुष्मान भारत" कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना नाम से एक नई योजना की घोषणा की है। इसके अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना के माध्यम से 10 करोड़ से अधिक गरीब परिवार (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) लाभान्वित होंगे और माध्यमिक और तृतीयक स्तर पर इन्हें प्रति परिवार 5 लाख रूपये तक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जायेगा। प्रस्तावित योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य कार्यक्रम है।

एक लंबे समय से ऑनलाइन सामान बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा खराब या नकली उत्पाद बेचने पर उन्हें ग्राहकों को पैसे वापिस लौटाने के लिये मजबूर करने वाले कानून बनाने की माँग की जा रही थी। इसी क्रम में ग्राहकों की समस्याओं को देखते हुए सरकार ने ई-कॉमर्स नीति बनाने का फैसला किया है। इस नीति का मसौदा 6 महीनों के अंदर लागू किया जायेगा। सरकार चाहती है कि नई नीति में ई-कॉमर्स कारोबार और ग्राहकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाये।

डाटा प्राइवेसी, कराधान, ऑनलाइन कारोबार से जुड़े तकनीकी पहलूओं, जैसेप्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सर्वर को देश में ही रखने और कनेक्टिविटी आदि को इस नीति में जगह दी जायेगी। नीति बनाने के लिये एक समिति का गठन किया गया है, जो 5 महीने में अपनी रिपोर्ट देगा। तदुपरांत, एक महीने के अंदर समिति की सिफ़ारिशों को अमलीजामा पहनाया जायेगा।

कहा जा सकता है कि मोदी सरकार ने अपने चार साल के कार्यकाल में अर्थव्यवस्था एवं सामाजिक सरोकार दोनों ही मोर्चों को मजबूत करने का काम किया है। वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उज्ज्वला योजना, मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के लिये ज्यादा राशि का आवंटन आदि के माध्यम से भी आम जनता को सशक्त बनाने का काम कर रही है।

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

'इसे मोदी इफेक्ट ही कहेंगे कि 30 महीने का काम 17 महीने में ही पूरा हो गया'

रमेश कुमार दुबे

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं की लेट-लेतीफी और उनकी बढ़ती लागत ने चिंता में डाल दिया। इसे देखते हुए उन्हों ने सांख्याकी एवं कार्यक्रम क्रियान्यनन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की। मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भूमि अधिग्रहण संबंधी जटिलताओं और पर्यावरण संबंधी मंजूरी में देरी अर्थात जयंती टैक्स के कारण देश की परियोजनाएं पिछड़ती जा रही हैं जिससे उनकी लागत भी बढ़ती जा रही है। मंत्रालय ने आकलन करके बताया कि बुनियादी ढांचा संबंधी 273 बड़ी परियोजनाओं में लेट-लतीफी के चलते उनकी लागत में 1.77 लाख करोड़ रूपये का इजाफा हो चुका है। परियोजनाओं में देरी करके मुनाफा कमाने के इस कुचक्र को तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूचना–प्रौद्योगिकी का इस्ते माल करते हुए उनकी निगरानी को सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध किया। नियोजन व निगरानी के लिए जीआईएस व अंतरिक्ष संबंधी चित्रों का उपयोग करने के साथ-साथ विभिन्नग स्तीरों की संख्याध कम करके धनराशि का कारगर प्रवाह सुनिश्चित किया गया है।

सामग्री की खरीद, निर्माण और रख-रखाव जैसे चरणों में

गुणवत्ताय संबंधी कठोर निगरानी की जाने लगी। हर महीने प्रगति कार्यक्रम के जरिए इसकी समीक्षा की जाने लगी। इसका नतीजा यह हुआ कि परियोजनाओं ने रफ्तार पकड़ ली। इसे मोदी सरकार के कार्यकाल में सड़क निर्माण में आई क्रांति के उदाहरण से समझा जा सकता है।

2013-14 में देश में हर साल 4260 किलोमीटर राजमार्गों (हाईवे) का निर्माण हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सख्तीं के चलते 2014-15 में 4410 किलोमीटर, 2015-16 में 6061 किलोमीटर और 2016-17 में 8231 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हुआ। 2017-18 में 17055 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के ठेके दिए गए और 9829 किलोमीटर सड़कें बनी।

यदि इसे रोजाना की दृष्टिक से देखें तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले देश में जहां हर रोज 11 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण हो रहा था, वहीं अब यह आंकड़ा 30 किलोमीटर प्रतिदिन से ज्यादा हो गया है। मोदी सरकार ने इस अनुपात को 40 किलोमीटर तक पहुंचाने का लक्ष्यज रखा है। इससे स्पाष्टा है कि मोदी सरकार के आने के बाद देश में हाईवे निर्माण ने रफ्तार पकड़ ली।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजमार्गों के साथ-साथ ग्रामीण सड़कों के निर्माण को भी प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था। शहरों से जुड़ सके। सरकार प्रति हेक्टे यर पैदावार बढ़ाने के उपाय करने के साथ-साथ फल, फूल, सब्जी् आदि के लिए प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, कोल्डे स्टोपरेज जैसे बुनियादी ढांचे में भारी निवेश कर रही है ताकि कृषि उपजों के कारोबार को बढ़ावा मिले।

प्रधानमंत्री इस बात को अच्छी तरह जानते हैं, ये निवेश तभी कारगर होंगे जब गांवों को बारहमासी सड़क संपर्क हासिल हो। जहां 2011-14 के दौरान हर रोज औसतन 70 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गईं, वहीं 2014-15 में यह आंकड़ा बढ़कर 100 किलोमीटर हो गया। 2016 में तो इसमें अभूतपूर्व तेजी आई और आज हर रोज 139 किलोमीटर सड़क बन रही है।

जो ग्रामीण सड़कें अब तक ठेकेदारों और स्थाईनीय नेताओं के रहमोकरम पर बनती थीं, उनकी गुणवत्ता़ सुनिश्चिोत करने के लिए प्रधानमंत्री ने बहुआयामी उपाय किए जिससे सड़कों की गुणवत्ताअ में सुधार हुआ। सड़क से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए "मेरी सड़क" नामक एप शुरू किया गया है। सरकार ने 2019 तक सवा दो लाख किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का लक्ष्यर रखा है।

परियोजनाओं की लेट-लतीफी के जरिए अपनी तिजोरी भरने वाली ताकतवर लॉबी से टक्कदर लेना इतना आसान काम नहीं था। मोदी सरकार ने इसके लिए कई नीतिगत बदलाव किया। सरकार ने सबसे पहले भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण क्लीयिरेंस तथा कोष की कमी जैसी समस्यानओं को दूर किया।

इसके अलावा उपग्रह आधारित सड़क परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली, सड़क निर्माण के लिए कंक्रीट का इस्तेहमाल, इलेक्ट्रा निक टॉल संग्रह, इनमप्रो जैसे सूचना तकनीक संबंधी कदम उठाए गए। इससे पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनी और सड़क निर्माण में क्रांति आ गई। इसे कहते हैं, 56 इंच सीने का कमाल। दुर्भाग्य़वश मोदी विरोधियों को यह उपलब्धियां दिखाई नहीं दे रही हैं।

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

चार सालों में सुशासन और विकास के हर मोर्चे पर कांग्रेस से बेहतर साबित हुई है मोदी सरकार !

अभय सिंह

2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपानीत राजग की सरकार सत्ता में आई। आजादी के इतने वर्षों बाद पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार को अकेले दम पर बहुमत मिला। नरेन्द्र मोदी के करिश्माई चेहरे के आगे विपक्ष ढेर हो गया। जनता ने मोदी को दिल खोलकर अपना समर्थन दिया। इसका मुख्य कारण था कांग्रेसनीत संप्रग सरकार की कुनीतियाँ। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार अपने चरम पर पहुँच गया था और हर तरफ सिर्फ घोटालों, लालफीताशाही, स्कैम्स की गूंज थी।

जनता इस निराशावादी माहौल को आशावादी रूप में पलटने को तैयार थी। इसके बाद मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र को एक उम्मीद मिली, यह उम्मीद थी परिवर्तन और विकास की। लेकिन जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना कतई सरल नहीं था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह जिम्मा उठाया और आज जब सरकार अपने चार वर्ष का उत्सव मना रही है, तो यह ना सिर्फ सरकार बल्कि देश की जनता के लिए भी विकास और सुशासन के चार वर्षों का उत्सव है।

इस सरकार ने जब कार्य करना प्रारंभ किया, उस दिन से ही इसने समग्र विकास की नींव रखी। सरकार निरंतर गरीब, पीड़ित और वंचित वर्ग के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से कार्य करती रही, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण जनधन, उज्ज्वला, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, स्वच्छ भारत मिशन, मुद्रा, स्टार्टअप इंडिया, अटल पेंशन आदि अनेक योजनाएं हैं। इन योजनाओं के आलोक में वर्तमान सरकार की विकास और लोक कल्याण की नीयत साफ दिखाई देती है।

यह विडंबना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम देश के गरीब तबके को बैंकिंग सिस्टम में नहीं ला पाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना से 31.52 करोड़ खाते खोले गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2014-17 के बीच पूरे विश्व में जितने नए बैंक खाते खुले उसमें अकेले भारत का 55 प्रतिशत हिस्सा रहा है। आलम यह है कि अब लगभग 80 फीसद वयस्कों के पास अपना बैंक अकाउंट है। इससे डिजिटल लेनदेन में भी इजाफा हुआ है।

यह विडंबना है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम देश के गरीब तबके को बैंकिंग सिस्टम में नहीं ला पाए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जनधन योजना से 31.52 करोड़ खाते खोले गए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 2014-17 के बीच पूरे विश्व में जितने नए बैंक खाते खुले उसमें अकेले भारत का 55 प्रतिशत हिस्सा रहा है। आलम यह है कि अब लगभग 80 फीसद वयस्कों के पास अपना बैंक अकाउंट है। इससे डिजिटल लेनदेन में भी इजाफा हुआ है।

इतना ही नहीं, सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर(डीबीटी) से यह भी सुनिश्चित किया कि अनेक योजनाओं के लाभार्थियों को बिना बिचौलियों की रुकावट के सीधे अपने खाते में पैसे प्राप्त हो जाएँ। पिछली सरकार के दौरान डीबीटी से सिर्फ 28 योजनाएँ ही जुड़ी थीं, लेकिन अब 433 योजनायें इससे जुड़ चुकी हैं और इससे देश को 83,000 करोड़ का लाभ हुआ है।

यहाँ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जिक्र करना भी समीचीन होगा। उज्ज्वला योजना के जरिये अबतक 3.8 करोड़ गरीब महिलाओं को मुफ्त में गैस सिलिंडर दिया गया है। स्पष्ट है, उज्ज्वला के माध्यम से करोड़ों गरीब परिवारों को धुआं रहित जीवन देना का काम हुआ है और योजना की सफलता को देखते हुए सरकार ने अब इसका लक्ष्य 5 करोड़ से बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया है।

देश को स्वच्छ बनाने के साथ-साथ महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान को सुरक्षित करने का कार्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के जरिये किया है। योजना के तहत अबतक 7.25 करोड़ से भी अधिक शौचालयों का निर्माण कार्य हुआ है और 3.6 लाख से ज्यादा गाँव एवं 17 से अधिक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। स्वच्छता अभियान की सफलता का अंदाज़ा इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि 2014 में जहाँ स्वच्छता कवरेज 35 प्रतिशत था, वह अब बढ़कर 85 प्रतिशत पर पहुँच गया है।

संप्रग सरकार लगातार यह कहते हुए नहीं थकती है कि 'आधार' हम लेकर आये। लेकिन जब मोदी सरकार ने आधार का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल कर बिचौलियों को ख़त्म करने का काम किया है, तो फिर आखिर परेशानी किस बात की। अगर आधार और डीबीटी से देश का पैसा बच रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है ?

आजादी के बाद लगभग साठ वर्षों तक सत्ता में रहते हुए भी कांग्रेस देश को अँधेरे से मुक्ति नहीं दिला पाई, लेकिन मोदी सरकार ने मात्र चार साल में यह काम कर दिखाया है। 2014 से पहले जो 18,500 गाँव अँधेरे में थे, वहाँ अब स्थिति बदल चुकी है। अब देश में सभी गांवों में बिजली आ चुकी है और सरकार हर घर तक बिजली पहुँचाने के अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इस कार्य के लिए विश्व बैंक ने भी मोदी सरकार की सराहना की है।

देश में पहली बार ऐसा नेतृत्व है, जो लोक-लुभावन नीतियों की बजाय जनता के हित में कड़े फैसले लेने में भी नहीं हिचकता। नोटबंदी और जीएसटी का फैसला इसी का उदाहरण है। नोटबंदी के बाद जहाँ देश में आयकरदाता 81 फीसद बढ़े, तो जीएसटी से पहले देश में 65 लाख पंजीकृत करदाता थे, जिनकी संख्या अब 1 करोड़ से अधिक हो गयी है। उसी तरह 2013-14 के मुकाबले 2017-18 में आयकर रिटर्न की संख्या 6.84 करोड़ हुई जो कि 80.5% अधिक है।

काग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, कालाधन, घोटालों का वर्चस्व था; वहीं मोदी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही कालेधन, भ्रष्टाचार पर प्रहार शुरू किया। इस सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही विशेष जाँच दल का गठन किया, स्विट्ज़रलैंड के साथ कालेधन से जुड़ी सूचनाएं साझा करने के लिए समझौता; कालाधन तथा कर अधिरोपण कानून-2015 को लागू करना; करीब तीन लाख कंपनियों पर कार्यवाही; बेनामी संपत्ति अधिनियम से कालेधन पर लगाम लगाना; आर्थिक भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लाना जिससे बैंकों को आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही करने में आसानी होगी; आदि ये सरकार के वो कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार और कालेधन के प्रति उसकी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को दिखाते हैं।

केंद्र की मोदी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए कृतसंकल्पित और देश के किसान की आय को 2022 तक दोगुनी करने के लिए

काग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार, कालाधन, घोटालों का वर्चस्व था; वहीं मोदी सरकार ने सत्ता में आने के साथ ही कालेधन, भ्रष्टाचार पर प्रहार शुरू किया। इस सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही विशेष जाँच दल का गठन किया, स्विट्ज़रलैंड के साथ कालेधन से जुड़ी सूचनाएं साझा करने के लिए समझौता; कालाधन तथा कर अधिरोपण कानून-2015 को लागू करना; करीब तीन लाख कंपनियों पर कार्यवाही; बेनामी संपत्ति अधिनियम से कालेधन पर लगाम लगाना; आर्थिक भगोड़ों की संपत्ति जब्त करने के लिए भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लाना जिससे बैंकों को आर्थिक अपराधियों पर कार्यवाही करने में आसानी होगी; आदि ये सरकार के वो कार्य हैं, जो भ्रष्टाचार और कालेधन के प्रति उसकी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को दिखाते हैं।

प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य किया जा रहा है। योजना के तहत अबतक 4.05 करोड़ किसान कवर किये जा चुके हैं और 379.06 लाख हेक्टेयर भूमि का बीमा किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के तहत 2014-18 के दौरान 5460.12 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई जो 2010-14 में 4698.65 करोड़ रूपए से 16.21 प्रतिशत अधिक है।

इसके अलावा ई-नाम योजना के जरिये 585 नियमित मंडियों को जोड़ने का काम हुआ है। चाहे मृदा स्वस्थ कार्ड हो या डीडी किसान चैनल हो, हर तरह से सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी सरकार ने बेहतर काम किया है। मिशन 'इन्द्रधनुष' से 80 लाख से अधिक गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया है। 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' से अबतक लगभग 104 जिलों में लड़का-लड़की अनुपात में सुधार हुआ है।

रोजगार के विषय पर बात करें तो आज भारत में 65% से अधिक की आबादी युवाओं की है, जिन्हें रोजगार देना महत्वपूर्ण हो जाता है। इसलिए मोदी सरकार ने ना सिर्फ रोजगार बल्कि स्वरोजगार पर भी बल दिया है। सरकार जॉब सीकर नहीं जॉब क्रिएटर के तौर पर युवाओं को देखती है। इसके लिए सरकार ने रोजगार सृजन के लिए कई कार्य प्रारंभ किये हैं, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का नए सिरे से निर्माण, मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया से स्वरोजगार का कार्य प्रगति पर है।

केंद्र सरकार नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए 'आयुष्मान भारत' जो कि विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा पहल है, लाई है। इसमें 50 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। सरकार गरीबों के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिये गरीब से गरीब परिवार को 2022 तक घर देने का लक्ष्य है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में ग्रामीण और शहरी इलाकों में करीब 1 करोड़ मकानों का निर्माण किया गया है। इसके अतिरिक्त 'प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना' से प्रत्येक गाँव को जोड़ने का कार्य प्रगति पर है और अब ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी वर्ष 2014 के 56 प्रतिशत से बढ़कर 82 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच चुकी है।

अगर हम विकास की बात करें, तो रेलवे को इससे अलग नहीं रखा जा सकता है और इसमें भी दुर्घटनाओं का प्रतिशत अगर कम होता है, तो निश्चित रूप से सरकार की दशा व दिशा सही है। आंकड़ों पर जाएँ तो 2013-14 के 118 के मुकाबले 2017-18 में 73 पर आ गयी है जो कि 62 प्रतिशत कम है। लेकिन सरकार अब भी इस दिशा में तेजी से कार्य कर रही है, जिससे दुर्घटनाएँ बिलकुल न हों। भारतीय रेलवे में एक नया आयम तब स्थापित हुआ जब मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को स्वीकृति मिली और इस पर कार्य भी तेजी से हो रहा है। जिसके बाद 8 घंटे से कम होकर मुंबई-अहमदाबाद की दुरी सिर्फ 2 घंटे में पूरी की जा सकेगी।

बहरहाल, चार वर्ष के कार्यकाल के बाद भी जनता का अटूट विश्वास मोदी सरकार पर बना हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी अब भी जनता की पहली पसंद बने हुए हैं। इन चार सालों में सुशासन और विकास के किसी भी मोर्चे पर अगर अवलोकन करें तो मोदी सरकार कांग्रेसनीत संप्रग सरकार से बेहतर साबित होती है। सरकार निरंतर 'सबका साथ सबका विकास' के अपने मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ रही है और देश के समग्र विकास के लिए प्रयासरत है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

सुशासन बना राजनीति का केंद्रीय बिंदु, आम नागरिकों के मन में बढ़ा आत्मसम्मान एवं विश्वास का भाव

भूपेंद्र यादव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के चार वर्ष पूरे हुए। इस कार्यकाल में मोदी सरकार ने जहां आम जनता से प्रभावी संवाद स्थापित किया वहीं आर्थिक निर्णयों एवं गरीब कल्याण कार्यक्रमों की सफलता और सामाजिक विषयों के प्रति जागरूकता ने देश के आम नागरिकों के मन में आत्मसम्मान एवं विश्वास का भाव बढ़ाया है। यही कारण है कि चार वर्षों में जन सामान्य की राजनीतिक विषयों में सक्रियता बढ़ी है। आम जन के मुद्दों से लेकर उत्तर-पूर्व के चुनाव तक के मसले राष्ट्रीय राजनीति की चर्चा के केंद्र बने हैं। जहां आम जन की अपेक्षाओं में वृद्धि हुई है वहीं युवा वर्ग में भारतीयता का भाव प्रभावी हुआ है। भाजपा का विभिन्न राज्यों में विस्तार जनभावना के सकारात्मक होने को दर्शाता है। मोदी सरकार के इन चार वर्षों के कार्यकाल को चार विषयों एवं उपलब्धियों में विभाजित करके देखा जा सकता है।

पहला, सुशासन का विषय देश की राजनीति का केंद्र बिंदु बना है। दूसरा, सामाजिक विषयों पर सरकार एवं जनता का संवाद बढ़ा है। तीसरा, समाज के हाशिये पर खड़े वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। चौथा, विश्व में भारत की साख में वृद्धि हुई है। किसी भी सरकार के सुशासन का पहला मानक होता है उसकी योजनाओं को एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाना। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला, उजाला, जन-धन, मुद्रा जैसी योजनाओं को एक तय समय में पूरा किया है। सुशासन का दूसरा मानक है चुनौतियों का साहस के साथ सामना करना और जनता के अधिकतम कल्याण के विषयों पर साहस भरे निर्णय लेना। केंद्र सरकार ने नोटबंदी, जीएसटी लागू

करने के साथ कड़े कानून के माध्यम से कालेधन के खिलाफ सख्ती से करवाई की है। सुशासन का तीसरा मानक है जड़ हो चुके कानूनों को समाप्त करके प्रभावी कानूनों एवं नीतियों को लागू करना।

इसीलिए आधार जैसे कानून के माध्यम से गरीब व्यक्तियों के हक को सुनिश्चित किया गया है। दिवालिया कानून लाकर विश्व समुदाय में भारत की साख को व्यवस्था के माध्यम से सुधारने का काम हुआ। आज कारोबारी सुगमता में भारत की रैंकिंग सौवें स्थान पर है। पहले भारत एक सौ तीसवें स्थान पर था। भूषण स्टील की बिक्री के जरिये बैंकों का पैसा, कर्मचारियों का वेतन और सरकार के पैसे दिवालिया कानून के माध्यम से वापस लिए गए। हालांकि केंद्र सरकार के सुशासन को हर विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों ने मुद्दा बनाया, पर न तो जनता ने उनका समर्थन किया और न ही किसी कानून को लागू करने के बाद सरकार को पीछे मुड़कर देखना पड़ा। विपक्ष की ओर से भले ही जातिवाद, संप्रदायवाद, वंशवाद की राजनीति का सहारा लेकर और विभेद पैदा कर जनता को उकसाने का काम किया जा रहा हो, लेकिन देश आज सुशासन को ही शासन में आने की कसौटी मान रहा है। सुशासन को राजनीति का केंद्र बिंदु बनाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली बड़ी उपलब्धि है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जनता के साथ प्रशासनिक स्तर के औपचारिक संबंध ही नहीं रखे, बल्कि सामाजिक कुरीतियों से लड़ने में जन भागीदारी को भी बढ़ाया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण सरकार द्वारा शुरू किया गया स्वच्छता का कार्यक्रम है। स्वच्छता पर प्रधानमंत्री के आग्रह से आज आम नागरिकों में सार्वजनिक स्थानों में सफाई का भाव बढ़ा है। स्वच्छता को लेकर देश की इच्छाशक्ति मजबूत हुई है। बीते चार वर्षों में योग दिवस जैसे आयोजनों में भी जन भागीदारी में भारी वृद्धि हुई है। इसके अलावा डिजिटल पेमेंट के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ी है। प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विकमंचों पर जिस प्रकार हिंदी का प्रयोग किया गया उससे देश के ग्रामीण युवाओं में भी आत्मविश्वास के भाव की वृद्धि हुई है। भारत में कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षा कानून लागू किया गया और मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। सैन्य बलों में महिलाओं की बढ़ती भूमिका से सामाजिक जीवन में महिलाओं के सक्रिय होने का माहौल बना है। इसी कारण स्वास्थ्य, स्वच्छता, ग्राम विकास, नारी सुरक्षा जैसे मामलों पर जनता ने सरकार के साथ मिलकर कदम बढ़ाया।

मेरा अनुभव है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 'मन की बात' के माध्यम से नौजवानों के कॅरियर, किसान, कृषि, ग्रामीण विकास और सामान्य व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार आदि विषयों पर बात होने से लोगों में राष्ट्र निर्माण के प्रति भागीदारी और सरोकार की भावना को और बल मिला है। यह दूसरी उल्लेखनीय उपलब्धि है। तीसरी उपलब्धि समाज के हाशिये पर खड़े लोगों का सशक्तीकरण करना है। उज्ज्वला योजना के तहत जहां गरीब के घरों में गैस सिलेंडर पहुंचाया गया वहीं शौचालयों का निर्माण कराकर एक बड़े वर्ग को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर प्रदान किया गया है। सरकार ने गरीबों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए हैं। पिछले 70 सालों के शासनकाल में कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को उनके अधिकारों से वंचित रखा। इस बार जब अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के संवैधानिक आयोग का विषय आया तो कांग्रेस ने विरोध किया। इससे कांग्रेस की कुटिल राजनीति उजागर होती है। लोकतंत्र की मजबूती 'सबका साथ सबका विकास' से ही संभव है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने सुशासन की उस धारणा को विकसित किया जिसने देश की अपेक्षाओं में वृद्धि की है।सत्ता में आते ही अपने शपथ-ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षेस देशों के प्रमुखों को आमंत्रित कर सबके साथ मधुर संबंध रखने की अपनी मंशा को स्पष्ट कर दिया था। साथ ही, एशिया में भारत के मजबूत होते नेतृत्व का संदेश भी दिया था। अब यह संदेश एशिया से निकलकर विश्व भर में प्रसारित हो रहा है और विभिन्न वैश्विक मंचों पर यह स्पष्ट हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत एक मजबूत देश के रूप में उभर रहा है। इसी वर्ष जनवरी में दावोस के मंच से विश्व के तमाम देशों के शासनाध्यक्षों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी का उद्घाटन भाषण विश्व समुदाय में भारत के मौजूदा नेतृत्व की स्वीकार्यता को दर्शाता है। इस भाषण में जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या पर प्रधानमंत्री ने जो स्पष्ट दृष्टिकोण रखा उसने विश्व समुदाय के समक्ष यह सिद्ध कर दिया कि अब किसी भी बड़े वैश्विकमसले पर भारत नेतृत्व करने में सक्षम हो चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि इस वक्त भारत के विश्व के सभी देशों से मधुर संबंध हैं।

एशिया की बात करें तो इसी साल गणतंत्र दिवस पर आसियान देशों के सभी शासनाध्यक्षों को आमंत्रित करके प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि एशिया में भारत ही बड़ा भाई है तो वहीं ब्रिक्स सम्मेलन के जरिये वैश्विक प्रभाव का संदेश दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय विदेश नीति ने सफलता के नवीन आयाम स्थापित किए हैं और मोदी विश्व पटल पर एक प्रभावी नेता के रूप में उभरे हैं। कुल मिलाकर लोक कल्याण का विषय हो या राष्ट्रीय सुरक्षा का अथवा राष्ट्रीय गौरव का, सभी मामलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकासपथ पर सतत अग्रसर है।

(लेखक राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं, दैनिक जागरण से साभार)

Discussion on "Dr Syama Prasad Mookerjee: Life and Legacy in the Present Context of West Bengal" at ICCR, Kolkata, West Bengal on 19th May 2018

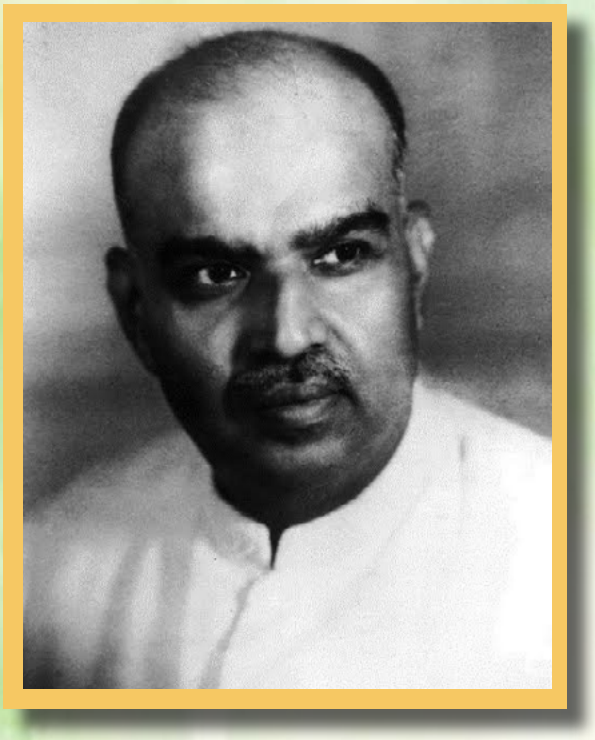

"The gigantic task of reconstruction, cultural, social, economic and political can be rendered possible thought coordinated efforts of bands of trained and disciplined efforts of bands of trained and disciplined Indians. Armed with the knowledge of Indian's past glory and greatness, her strength and weakness, it is they who can place before their country a programme of work, which while loyal to the fundamental traditions of India civilisation will be adapted to the changing conditions of the modern world."

-Dr. Syama Prasad Mookerjee
Convocation Address delivered at Gurukul Kangri Viswavidyalaya, Haridwar, 1943

Published By:
Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation
9, Ashoka Road New Delhi - 110001
E-mail: office@spmrf.org, Phone: 011-23005850